हिंदी पत्रकारिता का इतिहास

सेमेस्टर-1 : पेड न्यूज़

पेड न्यूज़ क्या है

पैसे लेकर विज्ञापन रूपी सामग्री को खबर के रूप में प्रकाशित किया जाए। दिखाया जाए। सुनाया जाए और पाठकों/दर्शकों/श्रोताओं को यह न बताया जाए कि यह खबर नहीं बल्कि विज्ञापन है, ऐसी सामग्री पेड न्यूज की श्रेणी में आती है।

भारत में इसकी शुरुआत

छत्तीसगढ़ में 1997 के विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत बताई जाती है। बाद के वर्षों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों के चुनाव में यह भ्रष्टाचार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश में अख़बारों ने पहली बार उगाही 2007 के विधानसभा चुनाव में की।

विशेषज्ञ की राय-एक

पत्रकार मृणाल पाण्डे लिखती हैं-पत्रकारिता जगत में 'पेड न्यूज' की झलकियाँ कई दशक पहले ही मिलनी शुरु हो गई थीं, जब कुछ पत्रकार पहले खेल और फिल्म-जगत फिर राजनीतिक दलों का उद्योग जगत से प्रोत्साहन पाकर पैसे या भेंट लेकर खास लोगों, पार्टियों और उपक्रमों पर सकारात्मक खबरें लिखने या उनके प्रतिद्वन्दियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने को राजी हो गए। कालक्रम में कुछ एक संस्थानों को लगा कि वे खुद इस बहती गंगा में हाथ क्यों न धोएं? चुनाव पास थे और विश्वव्यापी मंदी की अभूतपूर्व मार से उबरने के लिए सभी हाथ-पैर मार रहे थे। इसलिए चुनावी विज्ञापनों को चुपचाप खबर का जामा पहनाने की विधि को संस्थागत रूप दे दिया गया। परिणाम था-'पेड न्यूज'।

विशेषज्ञ, प्रेस परिषद की राय

- पत्रकार रामबहादुर राय कहते हैं-यह धंधा कम से कम दो दशक पुराना है। उसका चलन गुजरात और महाराष्ट्र में था। वहां चुनाव की रिपोर्टिंग में जो-जो गए, वे देख-समझ कर आए हैं। जो रोग पहले इक्के-दुक्के राज्यों में दबे-छुपे चल रहा था वह महामारी बनकर हिन्दी पट्टी में पिछले लोकसभा चुनाव (2009) में फैल गया। नया यही है। पर इतना ही नहीं है। इसकी जड़ें पाताल तक पहुंच गयी हैं। जो हम देख पाते हैं, वह बहुत छोटा हिस्सा है। इससे कोई बचा नहीं है। चाहे वह उम्मीदवार हो, चाहे कोई दल हो, चाहे मीडिया का कोई भी रूप हो और उसके मुखिया हों।

- भारतीय प्रेस परिषद ने बताया-पिछले छह दशकों से 'पेड न्यूज' का रूप विभिन्न मौकों पर उपहार स्वीकार करने, प्रायोजित विदेशी तथा स्वदेशी दौरे तथा अन्य लाभों जैसी चीजों से बदलकर प्रत्यक्ष भुगतान तक आ पहुंचा है।

- देश के अधिकतर समाचार पत्रों ने 2009 के लोकसभा चुनाव में गुपचुप तरीके से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से समझौता किया। उनसे प्रचार सामग्री को खबरों के रूप में प्रकाशित करने की बात की। इसके बदले में उनसे मोटी रकम की वसूली की। यह दोनों के हित में था कि वे न इसे जाहिर होने दें न इस भ्रष्टाचार की लिखा-पढ़ी करें।

पेड न्यूज़ को कैसे पहचानें

- लखनऊ में 'दैनिक जागरण' ने खबरों के पैकेज की शुरुआत 7 अप्रैल 2010 से की थी, जो चुनाव के अंतिम दिन तक चली। पत्र का यह पैकेज बसपा के डॉ. अखिलेश दास गुप्ता ने सबसे पहले खरीदा था। इसमें प्रचार (विज्ञापन) के मैटर का फांट हल्का बदल दिया गया था, लेकिन आम पाठक इसे समझ सकेगा, ऐसा नहीं लगता था।

- बसपा उम्मीदवार व पत्र के बीच पैकेज का धंधा फल-फूल रहा था कि इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने भी यह पैकेज खरीद लिया।

लखनऊ सीट से डा.अखिलेश दास गुप्ता का भारी बढ़त का दावा

लखनऊ, 28 अप्रैल (जागरण संवाद केन्द्र) : प्रमुख राजनैतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी लखनऊ संसदीय सीट पर इस बार बसपा के प्रत्याशी डा. अखिलेश दास गुप्ता का दावा है कि उन्हें अपनी रिकार्ड मतों से विजय सुनिश्चित नजर आने लगी है। इतना ही नहीं उनका यह भी दावा है कि इस बार यह भी तय है कि लखनऊ सीट पर पहले की तुलना में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा क्योंकि वोटरों में काफी उत्साह है। नये परिसीमन के बाद पूर्णतया शहरी सीट बन गई लखनऊ के वोटों के गुणा-भाग में भी इस बार काफी बदलाव आया है। इसी नाते पिछले चुनाव के आधार पर किये जाने वाले सारे पूर्वानुमान ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक दो स्थानीय उम्मीदवारों के बीच ही लड़ाई सिमटकर रह गई है लेकिन इस लड़ाई में भी बीते एक पखवारे से उनको साफतौर पर अपर हैण्ड नजर आने लगा है। बहुआयामी व्यक्तित्व, अनूठी कार्यशैली, संगठन क्षमता, साफ-सुथरी छवि तथा विकास से जुड़े सवालों को मुद्दा बना देने से मतदाता बेहद प्रभावित हैं। उनके पास समर्पित और उत्साही कार्यकर्ताओं की लम्बी-चौड़ी टीम है जिसने हवा का रुख पलटने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डा. अखिलेश दास गुप्ता का दावा है कि उनके द्वारा लखनऊ के विकास का जो ठोस खाका मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया

- **सभी वर्गों के मतदाताओं पर मजबूत पकड़**
- **व्यक्तित्व और संगठन क्षमता से वोटरों पर छाप पड़ने का दावा किया बसपा प्रत्याशी ने**

दिया है तथा खासतौर पर वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाकर मनोवैज्ञानिक लड़ाई में अन्य को चिन्ता में डाल दिया है। उनके अनुसार जमीनी आधार लगातार मजबूत हुआ है। खासतौर पर युवा मतदाताओं की संख्या करीब सात लाख है और वे बेहद निर्णायक भूमिका में हैं एवं उनके प्रचार में काफी बड़ी संख्या में शिक्षक, प्रोफेशनल तबके सम्बन्धित इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, वकील, सी.ए. से लेकर बुद्धिजीवी तक लगे हुये हैं। उनके दावे के मुताबिक विभिन्न सामाजिक और सेवा संगठन, मजदूर संगठनों के अतिरिक्त तमाम उच्चदराज लोग भी इस चुनाव में सक्रियता के साथ उनके संग नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि विख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबू बनारसी दास गुप्ता का पुत्र होने के नाते डा. अखिलेश दास गुप्ता ही उनके मददगार बनेंगे। जबकि स्थानीय होने का लाभ तो उनके दावे को मजबूती प्रदान कर रहा है। उनके अनुसार इन सारी बातों की झलक 27 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो सुंश्री मायावती की विशाल रैली में देखने को मिल गई जिसमें ज्यादा भीड़ जुटी थी।

उनका कहना है कि उनके समर्थक उन्हें करिश्माई मानते हैं और लखनऊ की गलियों में वे किसी परिचय के आज मोहताज नहीं हैं। लखनऊ के मेयर से अपना राजनीतिक कैरियर शुरु करने वाले डा. दास तीन बार संसद सदस्य (राज्यसभा) रहने के साथ केन्द्र में इस्पात राज्य मंत्री जैसी सफल भूमिका का भी निर्वहन कर चुके हैं। संसद के विभिन्न मंत्रालयों यथा वित्त, संचार, शहरी

हर किसी को लुभा रहा है रीता बहुगुणा का व्यक्तित्व

लखनऊ, 22 अप्रैल (जागरण संवाद केन्द्र) : राजधानी लखनऊ से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का मृदुल एवं सौम्य स्वभाव तथा उनकी ओजस्वी वाणी हर किसी को लुभा रही है। रीता जोशी जहां कहीं भी जा रही हैं लोग उन्हें हाथोंहाथ ले रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा का कोई पुराना साथी मिल जाता है तो पूछना ही क्या? लोग यादों में खो जाते हैं और तन, मन, धन से अपने पुराने साथी का कर्ज उतारने का वादा कर रहे हैं। रीता जोशी ने जन सम्पर्क करने में पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से शाम तक का समय जनसम्पर्क करने में लगाती हैं। इस बीच वे कांग्रेस मुख्यालय जाना नहीं भूलतीं कारण कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पूरे प्रदेश पर नजर रखनी है। बुधवार को सबेरे डा. जोशी जब बेगम हजरत महल पार्क में 'मार्निंग वाकर्स' के बीच पहुंची तो लोगों ने हाथोंहाथ ले लिया। रीता जोशी ने कहा कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय है। कल हजरतगंज थाना क्षेत्र में युवती से जिस प्रकार छेड़छाड़ हुई एवं बचाने वाले को पीटा गया वह 'कानून का राज' होने के दावे को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि शहर में दिनदहाड़े हत्या, लूट, छेड़ छाड़ जैसे संज्ञेय अपराध हो रहे हैं किन्तु पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। रीता जोशी के साथ रमेश मिश्रा, अशोक त्रिपाठी, ओम जायसवाल, राजीव शर्मा, विवेक शर्मा, अजीत वाजपेयी, रंजीत सिंह, मो. इम्तियाज, सहित तमाम कांग्रेसजनों ने जनसम्पर्क किया। डा. जोशी ने इसके बाद आनन्दनगर गयीं। यहां शहर अध्यक्ष श्याम किशोर शुक्ल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। यहां डा. जोशी ने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं उनका सही क्रियान्वयन हुआ होता तो प्रदेश विकास के पथ पर काफी आगे निकल गया होता किन्तु राज्य सरकार केंद्रीय रवैये के चलते प्रदेश पिछड़ गया। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले एक शिक्षिका के गायब होने की एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और अंत में शिक्षिका की लाश मिलती है। कैसे माना जाए कि आमजन सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि विकास और कानून व्यवस्था में सुधार का एक ही उपाय है कि कांग्रेस को जिताएं। पिता के सम्बन्धों की दुहाई देते हुए वे कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने हर जाति, धर्म और मजहब के लिए काम किया, पिता के पद चिन्हों पर चलकर वे भी सभी के लिए काम करेंगी। डा. जोशी के समर्थन में युवा कांग्रेस के मध्य जोन के अध्यक्ष पंकज तिवारी, आसिफ रिजवी, अंशू अवस्थी, विमल पाण्डेय, दिनेश यादव, संजय खान तथा अमित त्यागी ने जनसम्पर्क किया।

कांग्रेस को समर्थन : कोरी समाज ने कांग्रेस उम्मीदवार रीता जोशी को समर्थन देने का फैसला किया है। समाज के अध्यक्ष मोती लाल कोरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि वे बामसेफ के समय से दलित राजनीति से जुड़े रहे और दलितों विशेषकर कोरी समाज के हकों के लिए लड़ते रहे किन्तु न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा में उनकी बिरादरी को एक भी टिकट दिया गया। इसलिए बसपा छोड़कर कांग्रेस में आने का फैसला किया है। इतने दिन से राजनीति में रहकर उन्हें पता चल गया है कि कांग्रेस के अलावा दलितों के उत्थान की बात कोई नहीं करता। यादव महासभा की प्रदेश महासचिव और सपा की पूर्व प्रमुख महासचिव कमला देवी ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही महिलाओं व पिछड़ों का हित संभव है।

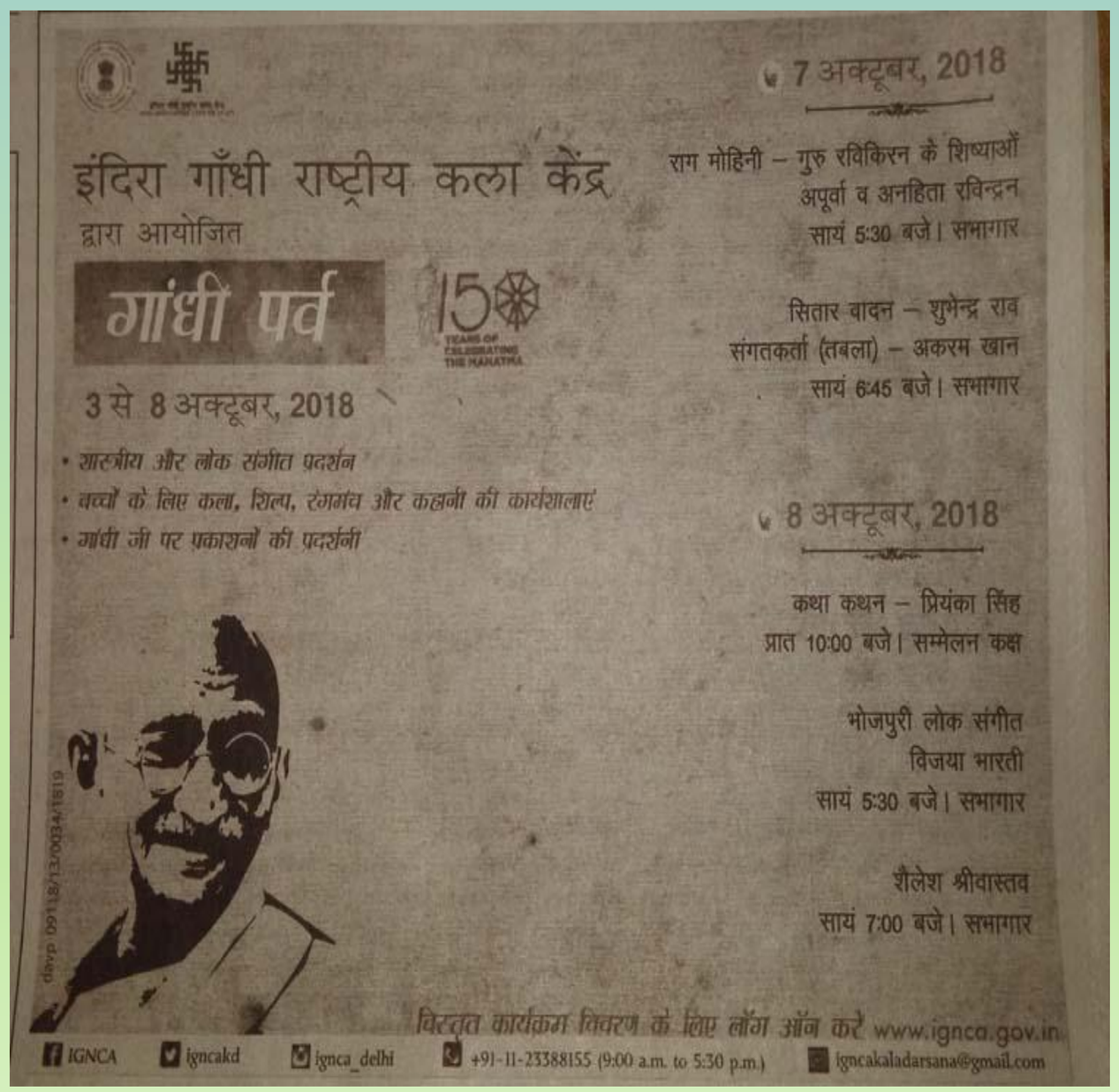

खबर और पेड न्यूज़ में अंतर

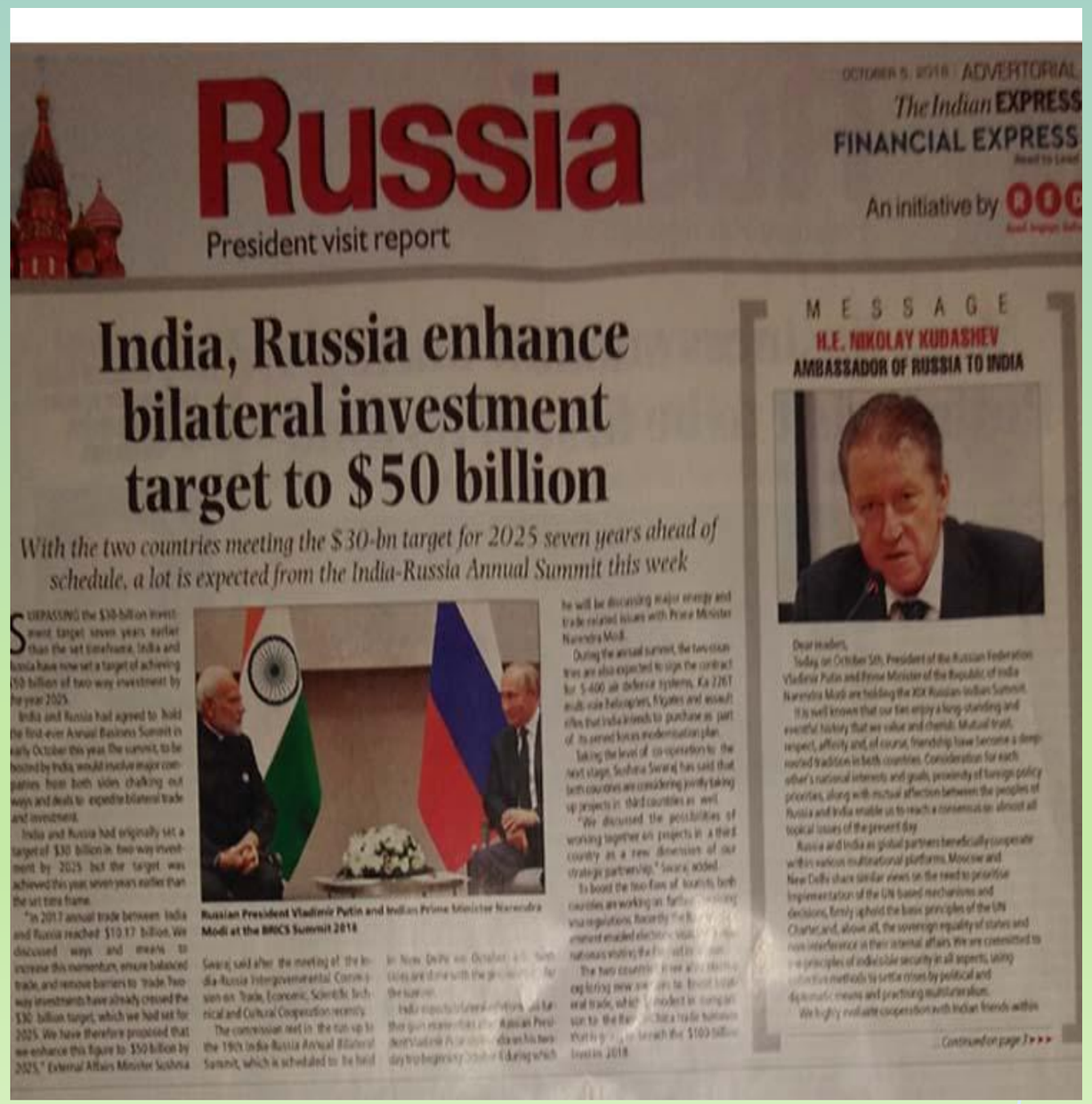

- ऊपर खबरों के रूप में प्रकाशित किए गए विज्ञापन में कहीं भी विज्ञापन का जिक्र नहीं है, लेकिन नीचे दिए दो विज्ञापनों में इसका बाकायदा जिक्र किया गया है। पाठक इससे पहचान सकते हैं कि अमुक सामग्री विज्ञापन है।

पेड न्यूज़ के खिलाफ़ अभियान

• इस धोखाधड़ी से समाचार पत्रों ने न सिर्फ अपने पाठकों के सूचना पाने के बुनियादी अधिकार को झुठलाया, लोकतंत्र के प्रति अपनी पहली जिम्मेदारी से भी मुँह मोड़ लिया। वे राजनीति के भ्रष्टाचार में खुद ही शामिल हो गए तो उस पर निगरानी क्या करेंगे? उसका भंडाफोड़ क्या करेंगे। अगर करेंगे भी तो उसका असर क्या होगा? उनकी विश्वसनीयता क्या रह गई है?

• इस बुराई के खिलाफ़ सबसे पहले समाचार पत्र "जनसत्ता" के सम्पादक रहे प्रभाष जोशी तनकर खड़े हुए। उनके साथ 'द हिन्दू' के पत्रकार रहे पी. साईंनाथ, पत्रकार रामबहादुर राय, परांजय गुहा ठाकुरता समेत चंद लोग साथ आए। इन लोगों ने पैसा लेकर प्रचार सामग्री को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने के खिलाफ मुहिम शुरू की। देश में घूम-घूम कर लोगों को उससे जोड़ने का काम किया

चौकीदार का चोर होना

प्रभाष जोशी

चुनाव की खबरों को बेचने का काला धंधा ऐसा नहीं कि अखबारों ने कोई छुपाते और लजाते हुए किया हो। छोटे-मोटे स्ट्रिंगर से लेकर संपादक और मालिक तक और उधर छुटभैये कार्यकर्ताओं से लेकर उम्मीदवार, उसकी पार्टी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक सब जानते थे कि अखबारों में चुनाव की खबरें पैसे और वह भी काले पैसे से छप रही हैं। राजनीतिक लोगों की बेशर्मी तो फिर भी समझी जा सकती है क्योंकि उनमें से अधिकतर अखबारों में छपे को अपना प्रचार मान कर ही चलते हैं। लेकिन अखबारों– खासकर हिंदी और अंग्रेजी के राष्ट्रीय दैनिक जो अपनी गिनती दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में और सबसे ज्यादा पाठकों वाले अखबारों में करवाते हैं और अपनी पत्रकारिता की तारीफ करते हुए खुद ही नहीं थकते– वे भी खबरों की अपनी पवित्र जगह बेचते हुए आंख की शर्म भी नहीं रखते थे।

कई अखबारों ने तो बाकायदा विज्ञापन के रेट कार्ड की तरह चुनाव कवरेज के भी रेट कार्ड छपवाए थे और वे न सिर्फ अपने स्टॉफ को दिए थे बल्कि उम्मीदवारों को भी दिए गए थे। दो राष्ट्रीय दैनिकों के छोटे स्थानीय संस्करणों के रेट कार्ड मेरे पास हैं। एक से पांच लाख तक के पैकेज में रंगीन और सादे कवरेज के रेट अलग-अलग मदों में दिए गए हैं। जैसे प्रचार अभियान के 8 गुणा 12 के रंगीन कवरेज के छह और सादे के चार हजार आठ सौ रुपए। जनसंपर्क के उतने ही कवरेज के तीस और चौबीस हजार। समर्थकों की अपील 9 गुणा 12 के सात और पांच हजार। जनसभा/रैली के 10 गुणा 16 के तीस और चौबीस हजार। प्रायोजित साक्षात्कार 7 गुणा 12 के साढ़े दस और साढ़े आठ हजार। मांग उदाहरण क्यों नहीं रखा। इकनॉमिक टाइम्स ने अपने रिश्वतखोर पत्रकारों को निकाल कर मिसाल क्यों नहीं बनाई कि ऐसा जो करेगा वह पत्रकारिता में टिक नहीं सकेगा? क्योंकि हम उसी के रास्ते पर चलते हैं जिसका रास्ता हमें अच्छा लगता है। अपने मालिक और प्रबंधन भ्रष्ट और रिश्वतखोर पत्रकारों का उदाहरण लेते हैं क्योंकि वे भी वही करना चाहते हैं जो उनके मुलाजिम ने पैसे बनाने के लिए किया।

भ्रष्टाचार को सदाचार बनाने की टाइम्स की दलील का मतलब है कि बलात्कार करना और उसकी इच्छा रखना स्वाभाविक है और हर आदमी चाहता है। इसलिए आपके घर की किसी मां, बेटी, बहन, भाभी आदि से कोई बलात्कार कर जाए तो नाहक हो हल्ला और पाखंड मत करो। बलात्कार को कानूनी रूप से मंजूर कर लो। उसके खिलाफ दंड और वर्जना मत बढ़ाओ। बलात्कार से पैदा हुए बच्चे/बच्ची का तिलक करो और वैध उत्तराधिकारी मान लो। इससे बलात्कार भ्रष्टाचार नहीं रहेगा सदाचार हो जाएगा। आखिर बलात्कार आदमी की सहज प्रवृत्ति है और स्वस्थ और सभ्य समाज सहज प्रवृत्तियों को मान कर ही विकास करता है। जैसे नवउदार पूंजीवाद लालच, सट्टाखोरी और धोखाधड़ी को आर्थिक विकास की प्रेरणाएं मानता है। और पंद्रह सितंबर दो हजार आठ के दिन वॉल स्ट्रीट के दिवाले के बाद भी वित्तीय पूंजीवाद को अमर और बाजार को स्वयंभू मानता है।

अब दिक्कत यह है कि खुले से खुले आदिवासी समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों में स्वतंत्रता और उदारता होती है। लेकिन एक बार विवाह हो जाए और बना रहे तो व्यभिचार बर्दाश्त नहीं होता। हत्याएं हो जाती हैं और स्त्री-पुरुष अलग हो जाते हैं क्योंकि गृहस्थ

अभियान का असर क्या हुआ

- प्रेस परिषद ने मामले की जांच और उसके निराकरण के उपाय सुझाने के लिए दो सदस्यीय (परांजय गुहा ठाकुरता, के.श्रीनिवास रेड्डी) समिति गठित की, जिसने राज्यों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसमें आरोपित लोगों व समाचार पत्रों के नाम शामिल किए। पत्रकारिता की बैंड बजाने के लिए उन्हें धिक्कारा। समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंपी तो आरोपितों की हिमायत करने वाली लॉबी ने उसे दबवा दिया।

- उस समय तक पेड न्यूज के खिलाफ मुखर रहने वाले परिषद अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एन. रे ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को दबाते हुए 12 सदस्यीय नई समिति का गठन कर दिया, जिसने मूल दस्तावेज से काट-छांट कर 12 पृष्ठीय गोलमोल रिपोर्ट तैयार की।

- प्रेस परिषद की रिपोर्ट पर मंत्री समूह गठित किया गया। संसद में सवाल-जवाब हुए। समूह ने इस मसले पर विचार किया। इसके बावजूद समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

- सांसद राव इंद्रजीत के सभापति वाली संसद की स्थायी समिति ने प्रेस परिषद का पुनरुद्धार करने पर बल देते हुए मीडिया, विशेषकर मीडिया की आय/राजस्व के स्रोत को सूचना का अधिकार के अधीन व लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने समेत अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की, लेकिन इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया।

पेड न्यूज़ के मामले में कार्रवाई

- पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 20 अक्तूबर 2011 को उत्तर प्रदेश के बिसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमलेश यादव को अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्हें 2007 के विधानसभा चुनावों में भारी भरकम राशि देकर अपने पक्ष में “अमर उजाला” और “दैनिक जागरण” में खबर प्रकाशित करवाने का दोषी पाया गया।

अमर उजाला

लखनऊ

ट्रेड वार चीन ने अर्थव्यवस्था में झोंके 109 अरब डॉलर....12

उत्तर प्रदेश

कामोव हेलीकॉप्टर भी रूस से खरीदेंगे

दूसरी बार इलाज कराने पर आधार जरूरी

आयुष्मान भारत : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अहमियत बरकरार

अब तक 47 हजार लोग योजना का ले चुके हैं लाभ

92,000

गुजरात में यूपी-बिहार वालों पर हमले, बढ़ा पलायन

साबरकांठा जिले में बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद छह जिलों में गैर-गुजरातियों को बनाया जा रहा निशाना, 342 गिरफ्तार

संभवत: त्योहारों की वजह से भी जा रहे लोग

टीईटी के लिए 22.75 लाख ने कराया पंजीकरण

।। नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएँ ।।

PLASTO

प्लास्टो है तो गॅरन्टी है।

पीने के पानी के लिए सुरक्षित

4 Layer PLASTO GOLD

नई पेशकश

PLASTO

GOLD 6 LAYER

EASY-CLEAN

नई दिल्ली, सोमवार 8 अक्टूबर 2018

दैनिक जागरण

www.jagran.com

जम्मू-कश्मीर में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 9

रूस से कामोव हेलीकॉप्टर भी लेगा भारत : जनरल रावत 11

टुडे प्रीमियम चाय

FREE

1 MULTIPURPOSE CONTAINER

With 250g. Today Premium Tea

250g pack

₹90/-

एक प्याली से जी ना भरे

TODAY TEA LIMITED

सरोकार

चार साल में 10 हजार उपाय कर कारोबार आसान बनाया : मोदी

कहा-बदल रहा है देश, अब विश्व के आर्थिक विकास का इंजन होगा भारत

बिहार में कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को मनचलों ने पीटा

इंडिगो के सर्वर में खराबी से दो घंटे तक परेशान हुए यात्री

अंदर पढ़ें

एक पक्ष दोषी, दूसरा बरी

- पेड न्यूज के कारण किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किए जाने का यह पहला मामला था। इसी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रहे योगेंद्र कुमार ने “अमर उजाला” और “दैनिक जागरण” के खिलाफ पेड न्यूज छापने की शिकायत की थी।

- यह पेड न्यूज चुनाव तिथि से ठीक एक दिन पहले उमलेश यादव को मदद पहुंचाने के लिए मकसद से प्रकाशित की गई थी। अहम बात यह कि इस मामले में अपराध करने के लिए उकसाने वाला पक्ष दण्डित किया गया, जबकि अपराध को अंजाम देने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

- चुनाव आयोग ने किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पेड न्यूज को प्रकाशित किए जाने एवं उसे प्रकाशित किए जाने के उकसाने के कृत्य को 1951 के अधिनियम के अध्याय-तीन के भाग-सात के अंतर्गत शामिल किए जाने की सिफारिश की है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष के कड़े कारावास का प्रावधान हो।

समाप्त

:: प्रस्तोता ::

डॉ. अटल तिवारी

हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार

रामलाल आनंद महाविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय